भारत बना विष्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

डॉ0 रंजना नीलिमा कच्छप

सहायक प्राध्यापक अर्थषास्त्र
षा0नवीन कन्या महाविद्यालय
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया(छ0ग0)

संक्षिप्त सार :
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। भारत की वास्तविक GDP औसतन 6.5 प्रतिषत से 7 प्रतिषत की दर से बढेगी। इस निरंतरता के कारण भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जायेगी। भारत की कार्यषील आयु वाली जनसंख्या 15 से 64 वर्ष अभी अपने चरम पर है। यह युवा षक्ति न केवल उत्पादन को बढ़ायेगी बल्कि घरेलू उपभोग को भी प्रेरित करेगी।वैष्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केन्द्र के रूप में देख रही है। PLI योजनाओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में FDI में वृद्धि आने की संभावना है। भारत के युवाओं में कौषल क्षमता का अभाव है अतः कौषल विकास पर विषेष जोर देना होगा। भविष्य में भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी, तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जलवायु परिवर्तन भी मौजूद है। विशेषज्ञ का मानना है कि यदि सुधारों की गति जारी रही तो आने वाले वर्षो में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन सकती है।

मुख्य षब्द –: रोजगार, नवाचार, खाद्यान आपूर्ति, संतुलित आर्थिक विकास, कौषल विकास

प्रस्तावनाः

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने घोषणा की कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विष्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। भारत की नॉमिनल जीडीपी अब लगभग $4.18 ट्रिलियन से $4.51 ट्रिलियन के बीच पहुंच गई है। यह उपलब्धि ऐसे दौर में है जब वैष्विक उद्योग मंदी, युद्ध और अर्थव्यवस्था के दबाव से जूझ रहा है। वर्ष 2025 के अंत तक वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहे। जबकि भारत ने कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। यह बदलाव केवल आर्थिक आंकड़ों का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का संकेत भी है। विशेषज्ञ का मानना है कि भारत की यह स्थिति उसके माध्यमिक विकास मॉडल और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है। जो इस प्रकार देखा जा सकता है–जीडीपी में वृद्धि दर 7% रही, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अधिक सरल और प्रभावशाली बनाया गया जिससे कर संग्रह में तेजी आयी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया और आयात पर काम किया। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया जिससे नीतिगत सुधार हुए। औद्योगिक उत्पान बढ़ा जिसमें ऑटो मोबाईल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में वृद्धि, मोबाईल फोन निर्माण में वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र, राजमार्गो एक्सप्रेसवे, रेल्वे स्टेशन का विस्तार, हवाई जहाजों का आधुनिकरण हुआ। वास्तुशिल्प के विक्रय में वृद्धि, बॉस की खेती, आईटी सीमेंट, यूक्रेन, इंजीनियरिंग उत्पाद में वृद्धि, सेवा क्षेत्र ओर डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई पहचान मिली, गरीबी में कमी तथा आय में वृद्धि हुई, रोजगार विकास समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय साख में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भविष्य में भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी, तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार

और जलवायु परिवर्तन भी मौजूद है। विशेषज्ञ का मानना है कि यदि सुधारों की गति जारी रही तो आने वाले वर्षो में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन सकती है।

उद्देश्य (1) भारत की तीव्र प्रगति के कारण और रणनीतियों का अध्ययन करना।
(2) भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में प्रमुख क्षेत्रों के योगदान का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति :– यह अध्ययन द्वितीयक स्त्रोतों के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं तथा समसामयिकी समाचारों पर आधारित है।

तीव्र प्रगति के कारण और रणनीतियां

1. निरंतर उच्च विकास दर (High Growth Rate)

भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनियां की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जहाँ विकसित देशों की वृद्धि दर 1% से 3% के बीच रही है, वहीं भारत ने 6.2% से 8.2% तक की विकास दर दर्ज की है।

2. घरेलू माँग और निजी खपत (Strong Domestic Demand)

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर आधारित है। मध्यम वर्ग का विस्तार–बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि ने बाजार माँग को बनाए रखा है।

निजी उपयोग– भारत की जीडीपी में निजी अंतिम उपयोग व्यय (PFCE) की हिस्सेदारी लगभग 60% है जो इसे बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता है।

3. डिजिटल क्रांति और तकनीकी सेवायें (Digital Transformation)

फिनटेक और UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत दुनियां का नेतृत्व कर रहा है। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकरण हुआ है।

IT और सेवा क्षेत्र– भारत का सेवा क्षेत्र (Service Sector)जीडीपी में 50% से अधिक का योगदान देता है। टीसी एस और इंफोसिस जैसी कंपनियों ने वैष्विक स्तर पर भारत का दबदबा बनाया है।

4. बुनियादि ढ़ाँचे में भारी निवेश (Infrastructure boost)

सरकार ने गतिशक्ति और 'पी.एल.आई.' (PLI) स्कीम जैसी योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढ़ाँचे पर भारी खर्च किया है। सड़कों, रेल्वे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जाल ने व्यापार करने की लागत (Cost of Doing Business)को कम किया है।

मेक इन इंडिया – विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया है, जिससे एप्पल और सेमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी इकाईयाँ स्थापित की है।

5. आर्थिक सुधार (Structural Reforms)

पिछले दशक में किये गये बड़े आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत की।

GST : एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ।

IBC (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) इससे बैंकिग क्षेत्र में फसे कर्ज की समस्या सुलझी।

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौतीः– निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स दरों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया गया।

अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति 2026

देश	जीडीपी (अनुमानित ट्रिलियन $)	स्थान
अमेरिका	$ 30.50 - $31.82	1
चीन	$ 19.23 - $20.65	2
जर्मनी	$ 4.74 - $5.33	3
भारत	$ 4.18 - $4.51	4
जापान	$ 4.11 - $ 4.46	5

चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बनाने में प्रमुख क्षेत्रों का योगदान

1 सेवा क्षेत्र (Service Sector)

अर्थव्यस्था का इंजन यह भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है जो कुल सकल मूल्य वर्धित (GVA) का लगभग 55% हिस्सा कवर करता है।

- IT और डिजिटल सेवायें– भारत दुनियाँ का आउटसोर्सिग हब है। सॉफ्टवेयर निर्यात और डिजिटल प्लेटफार्म ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
- फिनटेक और बैंकिग – UPI और डिजिटल बैंकिग ने वित्तीय समावेश को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति दी है। विकास दर– सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में औसत 8.3% की वृद्धि देखी गई है (05:00)

2. औद्योगिक और विनिमय क्षेत्र (Industrial & Manufacturing Sector)

इसका जीडीपी में योगदान लगभग 28% है। सरकार के मेक इन इंडिया और PLI (Production linked Incentive) स्कीम ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाईलः– भारत अब दुनियाँ का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है।
- बुनियादी ढ़ाँचा (Infrastructure) सीमेंट, स्टील और निर्माण (Construction) गतिविधियों में भारी निवेश ने औद्योगिक विकास को मजबूती दी है।
- सेमीकंडक्टर : 2026 तक भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है।

3. कृषि और संबंध क्षेत्र (Agriculture & Allied Sector)

यद्यपि जीडीपी में इसका योगदान लगभग 16-19% है लेकिन यह देश की 46% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करता है।

- खाद्य सुरक्षा : भारत अनाज, फल और दूध के उत्पादन अग्रणी बना हुआ है।
- आधुनिकीकरण : कृषि में तकनीक का उपयोग और मत्स्य पालन (Fisheries) जैसे संबंध क्षेत्रों में 8.7% जैसी उच्च वृद्धि दर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष योगदान है।

क्षेत्रवार योगदान का सारांश (2024–25)

क्षेत्र	जीडीपी में योगदान %	मुख्य चालक
सेवा क्षेत्र	55%	IT बैंकिग, पर्यटन, दुरसंचार
उद्योग	28%	विनिर्माण, निर्माण, बिजली
कृषि	17%	फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन

2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ना और $7 ट्रिलियन के आँकड़े को पार करना है।

1. विनिर्माण (Manufacturing) और मेक इन इंडिया भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर है। इसके लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों जैसे (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, और ऑटोमोबाइल) में भारी निवेश किया जा रहा है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और निर्यात में वृद्धि हो।

2. बुनियादि ढ़ाँचा (Infrastructure) विकास– सरकार PM गति षक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर काम कर रही है।

- रेलवे 20–30 तक हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर और 100: विद्युतीकरण का लक्ष्य हाईवे नेटवर्क का विस्तार और एक्सप्रेसवे सड़क नेशनल का निर्माण
- विमान : हवाई अड्डो की संख्या को 150 से बढ़ाकर 200 + करना

3. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादि ढ़ाँचा (DPI)

- भारत की डिजिटल इकोनॉमी इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

- UPI आधार और ओ.एन.डी.सी. (ONDC) जैसे प्लेटफॉर्मर्स ने वित्तीय समावेषन और ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया है। AI और क्लाइड कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग से उत्पादकता में भारी सुधार की उम्मीद है।

4. ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) 2030 तक भारत ने अपनी गैर–जीवश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा पर निवेश से न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

5. सामाजिक और आर्थिक सुधार

- कौशल विकास : युवा कार्यबल (Demographic Dividend) को कुशल बनाना ताकि वे वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकें।
- व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) श्रम कानूनों का सरलीकरण और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार और देरी को कम करना।
- निर्यात : नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जैसे UK और यूरोपीय संघ के साथ समझौते करना।

आर्थिक लक्ष्य का सारांष

मील का पत्थर	अनुमानित वर्ष	विवरण
चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था	2025–26	$4.18 ट्रिलियन (जापान को पीछे छोड़ा)
तीसरी बड़ी अथव्यवस्था	2028–30	जर्मनी को पिछे छोड़ने का लक्ष्य
प्रति व्यक्ति आय	2030	$4.000(अपर –मिडल इनकम देष की श्रेणी)

निष्कर्ष –:

भविष्य में भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है जिसमें लगभग 60 प्रतिषत आबादी 15–59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के हैं जो 2030 तक 68.9 प्रतिषत पर पहुंचने का अनुमान है। षिक्षा के क्षेत्र में एन ई. पी. पूरे भारत में संचालित है जिसमें कौषल विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है यह रोजगारोन्मुखी षिक्षा के रूप उभरकर सामने आई है। विशेषज्ञ का मानना है कि यदि सुधारों की गति जारी रही तो आने वाले वर्षो में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन सकती है।

संदर्भ ग्रंथ

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट 2026।
2. https://www.drishtiias.com
3. https://www.usthadian.com
4. https://www.sanskritiias.com
5. https://www.thecsrjournal.in भारत बना 2025 में दुनियां की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकषक्ति